

ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रपॉर्ट 2023

प्रलिस के लिये:

यूनियर्सल डक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट (UDHR), मानवाधिकारों को सशक्त बनाने के लिये भारत की पहल, हेलसिकी समझौता

मेन्स के लिये:

मानवाधिकारों के लिये भारत की वभिन्न पहल और हाल के वर्षों में देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन के वरिधाभासी उदाहरण ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रपॉर्ट 2023 (33वाँ संस्करण) में कहा कि भारतीय अधिकारियों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकर्ता समूहों एवं मीडिया पर अपनी कार्यवाही को अधिक "तीव्र और व्यापक" कर दिया ।

- इसमें यह भी दावा किया गया है कि वर्तमान केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी ने अल्पसंख्यकों को दबाने हेतु अपमानजनक और भेदभावपूर्ण नीतियों का इस्तेमाल किया ।

ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है?

- ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में "हेलसिकी वॉच" के रूप में हुई थी, शुरू में इसका उद्देश्य हेलसिकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अधिकारों के हनन की जाँच करना था ।
 - वर्तमान में इसका दायरा दुनिया भर के लगभग 100 देशों में वस्तितरति हो गया है ।
 - इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है ।
- हेलसिकी समझौता (1975), यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर पहले सम्मेलन (अब यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन) के समापन पर हेलसिकी, फिनलैंड में हस्ताक्षरति एक प्रमुख राजनयिक समझौता था ।
 - मुख्य रूप से सोवियत और पश्चिमी ब्लॉक के बीच तनाव को कम करने हेतु हेलसिकी समझौते पर कनाडा, अमेरिका एवं यूरोप के सभी देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे ।
 - समझौते के तहत 35 हस्ताक्षरकर्ता देशों ने मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का वचन दिया था ।

वर्ल्ड रपॉर्ट 2023 के भारत वशिष्ट नषिकर्ष:

- सरकार द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन:
 - रपॉर्ट में पाया गया कि केंद्र सरकार हट्टि बहुसंख्यक वचिरधारा को बढ़ावा दे रही है तथा अधिकारियों और समर्थकों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खलिाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने एवं कभी-कभी हसिक कार्रवाई हेतु भी उकसाती है ।
 - इसने महिलाओं के खलिाफ हसिा के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतसरकार के भेदभावपूर्ण रुख (बलिकसि बानो बलात्कार के दोषियों की रहिाई) को उजागर किया है ।
 - अनुच्छेद 370 को हटाने तथा बाद में दो केंद्रशासति प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के नरिमाण के 3 साल पश्चात् भी "सरकार ने दोनों केंद्रशासति प्रदेशों में स्वतंत्र अभवियक्ती एवं शांतपूरण समागम को प्रतबिंधति करना जारी रखा" है ।
 - प्राधिकारी वर्गों ने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को "मनमाने ढंग से" हरिसत में लेने के लिये जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (J&K Public Safety Act) एवं गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967 का भी इस्तेमाल किया ।
 - इसने कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक हट्टि और सखि समुदायों पर संदगिध आतंकवादी हमलों का भी उल्लेख किया है ।
- सर्वोच्च न्यायालय के वभिन्न नरिणियों का स्वागत:

- HRW ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए त्वरति उदार कदमों की सराहना की, जैसे औपनिवेशिक युग के [राजद्रोह कानून](#) के सभी उपयोग को रोकने का निर्णय।
- इसने वैवाहिक स्थितिकी परवाह कयि बना [सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार](#) देने तथा समान-लगि वाले युगल, एकल माता-पति और अन्य परिवारों को शामिल करने हेतु परिवार की परभाषा को व्यापक बनाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कयि।
 - हालाँकि शैक्षणिक संस्थानों में [मुस्लिम छात्राओं के हजिाब पहनने के अधिकार](#) पर सर्वोच्च न्यायालय किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा।

मानवाधिकारों के लयि भारत की पहलें:

- संवधान में प्रावधान:
 - [मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 14 से 32](#)
 - [राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांत](#): संवधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के वरिद्ध सुरक्षा, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार, मुफ्त और अनविरय शिक्षा का अधिकार एवं मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार आदि शामिल हैं।
- सांविधिक प्रावधान:
 - [मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम \(PHRA\), 1993](#) (वर्ष 2019 में संशोधित): NHRC की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई थी।
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भूमिका:
 - भारत ने [मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा \(UDHR\)](#) के प्रारूपण में सक्रिय रूप से भाग लिया।
 - भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICESCR) तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) का भी अनुसमर्थन कयि है।

अन्य समान रिपोर्ट:

- [भारत- 2021 पर मानवाधिकार रिपोर्ट](#) (अमेरिकी वरिदेश वभाग द्वारा)।
- [फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट](#) (अमेरिका स्थित फ्रीडम हाउस द्वारा)।
- [डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022](#) (यूनियर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, स्वीडन में वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा)।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संवधान का नमिनलखिति में से कौन-सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है या प्रतबिबिति करता है? (2020)

1. प्रस्तावना
2. राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांत
3. मौलिक कर्तव्य

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा में काफी हद तक योगदान दयि है, फरि भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरिद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक एवं व्यावहारिक सीमाओं का वशिलेण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजयि। (2021)

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/human-rights-watch-s-world-report-2023>

